रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एम0 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 30 मार्च, 1998/9 चैत्र, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 30 मार्च, 1998

संख्या 1-20/98-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1997 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1998 (1998 का

1251-राजपत्र/98-30-3-98—1,278. मूल्य : 1 रुपया ।

विधेयक संख्यांक 2) जो दिनांक 30 मार्च, 1998 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,

अजय भण्डारी,
सचिव ।

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

1998 का विधेयक संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1998

वित्तीय वर्ष 1998-99 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के निकालने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 1998 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए 13,40,00 55,000 रुपये की राशि निकालना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग 13,40,00,55,000 रुपये (तेरह अरब, चालीस करोड़, पचपन हजार रुपये) है, वित्तीय वर्ष 1998-99 के अप्रैल से जुलाई मास की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित संदायों के विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए निकाली जाएं ।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का विनियोग, अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा और निर्वाचन (राजस्व)	1,88,96,000	3,26,000	1,92,22,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद् (राजस्व)	1,11,20,000	30,73,000	1,41,93,000
3	न्याय प्रशासन (राजस्व)	4,76,23,000	1,25,68,000	6,01,91,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	71,31,38,000	57,96,000	71,89,34,000
	(पूंजी)	5,06,000	—	5,06,000
5	भू-राजस्व (राजस्व)	24,80,70,000	—	24,80,70,000
	(पूंजी)	4,63,000	—	4,63,000
6	आबकारी और कराधान (राजस्व)	5,02,61,000	—	5,02,61,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	43,76,46,000	—	43,76,46,000
8	शिक्षा, खेलें तथा कला (राजस्व)	1,63,18,41,000	—	1,63,18,41,000
	और संस्कृति (पूंजी)	2,49,67,000	—	2,49,67,000
9	चिकित्सा और परिवार (राजस्व)	64,29,88,000	—	64,29,88,000
	कल्याण (पूंजी)	5,87,66,000	—	5,87,66,000
10	लोक निर्माण (राजस्व)	37,38,55,000	—	37,38,55,000
	(पूंजी)	3,43,60,000	—	3,43,60,000
11	कृषि (राजस्व)	29,36,68,000	—	29,36,68,000
	(पूंजी)	6,22,50,000	—	6,22,50,000
12	सिंचाई और बाढ़ (राजस्व)	20,26,03,000	—	20,26,03,000
	नियन्त्रण (पूंजी)	8,82,94,000	—	8,82,94,000
13	भूमि और जल संरक्षण (राजस्व)	5,75,47,000	—	5,75,47,000
	(पूंजी)	33,000	—	33,000
14	पशुपालन और दुग्ध (राजस्व)	13,34,61,000	—	13,34,61,000
	विकास (पूंजी)	49,00,000	—	49,00,000
15	मत्स्य (राजस्व)	1,27,43,000	—	1,27,43,000
	(पूंजी)	32,41,000	—	32,41,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	73,85,23,000	—	73,85,23,000
	(पूंजी)	78,90,000	—	78,90,000
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	39,39,26,000	—	39,39,26,000
	(पूंजी)	40,71,72,000	—	40,71,72,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	13,12,88,000	—	13,12,88,000
		(पूंजी)	40,34,000	—	40,34,000
19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पोषाहार सहित)	(राजस्व)	21,80,79,000	—	21,80,79,000
		(पूंजी)	95,17,000	—	95,17,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	33,18,07,000	—	33,18,07,000
		(पूंजी)	1,67,000	—	1,67,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	3,87,44,000	—	3,87,44,000
		(पूंजी)	1,06,16,000	—	1,06,16,000
22	खाद्य और भाण्डागारण	(राजस्व)	6,28,01,000	—	6,28,01,000
		(पूंजी)	10,34,00,000	—	10,34,00,000
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	27,66,67,000	—	27,66 67,000
		(पूंजी)	51,81,67,000	—	51,81,67,000
24	लेखन सामग्री और मुद्रण	(राजस्व)	3,02,77,000	—	3,02,77,000
		(पूंजी)	7,17,000	—	7,17,000
25	सड़क, जल परिवहन और नागर विमानन	(राजस्व)	8,64,86,000	—	8,64,86,000
		(पूंजी)	5,44,95,000	—	5,44,95,000
26	पर्यटन और आतिथ्य संगठन	(राजस्व)	1,96,51,000	—	1,96,51,000
		(पूंजी)	1,36,67,000	—	1,36,67,000
27	श्रम और रोजगार	(राजस्व)	3,84,59,000	—	3,84,59,000
		(पूंजी)	47,00,000	—	47,00,000
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	53,01,72,000	—	53,01,72,000
		(पूंजी)	29,10,87,000	—	29,10,87,000
29	वित्त	(राजस्व)	80,09,16,000	1,83,97,22,000	2,64,06,38,000
		(पूंजी)	—	50,98,20,000	50,98,20,000
30	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	7,62,17,000	—	7,62,17,000
31	जन-जातीय विकास	(राजस्व)	46,33,83,000	—	46,33,83,000
		(पूंजी)	21,24,85,000	—	21,24,85,000
	कुल जोड़ ..		11,02,87,50,000	2,37,13,05,000	13,40,00,55,000
	(राजस्व) ..		9,03,66,39,000	1,86,14,85,000	10,89,81,24,000
	(पूंजी) ..		1,99,21,11,000	50,98,20,000	2,50,19,31,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधयक भारत के संविधान क अनुच्छेद 203 और 204 के अधीन विहित प्रक्रिया के पूर्ण होने तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 206 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम चार मास अप्रैल से जुलाई के लिए अपेक्षित धन के ऐसे व्यय को जो संचित निधि पर प्रभारित है और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्यय को पूरा करने के लिए, निकालने का उपबन्ध करने के लिए पुर:स्थापित है । मांगे गये धन में वर्ष 1998-99 की वस्तुत: नई स्कीमों का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

नियमित बजट विधान सभा द्वारा जुलाई, 1998 में पारित किया जाना है । अत: अप्रैल से जुलाई, 1998 के लिए लेखा अनुदान अभिप्राप्त किया जा रहा है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
30 मार्च, 1998

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल संख्या वित्त-ए-सी (1)-1/98]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1998 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जान क पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुर:स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1998

वित्तीय वर्ष 1998-99 के कुछ भाग क लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के निकालने का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

प्रम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
30 मार्च, 1998.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Bill No. 2 of 1998.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1998

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year 1998-99.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1998.

Withdrawal of Rs. 13,40,00, 55,000 from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1998-99.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 13,40,00,55,000 (Thirteen hundred and forty crores, fifty five thousands rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the months of April to July of the financial year 1998-99 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of the Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
De-mand No.	Services and purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	1,88,96,000	3,26,000	1,92,22,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	1,11,20,000	30,73,000	1,41,93,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	4,76,23,000	1,25,68,000	6,01,91,000
4	General Adminis-tration	(Revenue)	71,31,38,000	57,96,000	71,89,34,000
		(Capital)	5,06,000	—	5,06,000
5	Land Revenue	(Revenue)	24,80,70,000	—	24,80,70,000
		(Capital)	4,63,000		4,63,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	5,02,61,000	—	5,02,61,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	43,76,46,000	—	43,76,46,000
8	Education, Sports, Arts and Culture	(Revenue)	1,63,18,41,000	—	1,63,18,41,000
		(Capital)	2,49,67,000	—	2,49,67,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	64,29,88,000	—	64,29,88,000
		(Capital)	5,87,66,000	—	5,87,66,000
10	Public Works	(Revenue)	37,38,55,000	—	37,38,55,000
		(Capital)	3,43,60,000	—	3,43,60,000
11	Agriculture	(Revenue)	29,36,68,000	—	29,36,68,000
		(Capital)	6,22,50,000	—	6,22,50,000
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	20,26,03,000	—	20,26,03,000
		(Capital)	8,82,94,000	—	8,82,94,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	5,75,47,000	—	5,75,47,000
		(Capital)	33,000	—	33,000
14	Animal Husbandry and Dairy Develop-ment	(Revenue)	13,34,61,000	—	13,34,61,000
		(Capital)	49,00,000	—	49,00,000
15	Fisheries	(Revenue)	1,27,43,000	—	1,27,43,000
		(Capital)	32,41,000	—	32,41,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	73,85,23,000	—	73,85,23,000
		(Capital)	78,90,000	—	78,90,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	39,39,26,000	—	39,39,26,000
		(Capital)	40,71,72,000	—	40,71,72,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	13,12,88,000	—	13,12,88,000
		(Capital)	40,34,000	—	40,34,000
19	Social Security and Welfare (Including Nutrition)	(Revenue)	21,80,79,000	—	21,80,79,000
		(Capital)	95,17,000	—	95,17,000

1	2		3		
			Rs	Rs.	Rs.
20	Rural Development	(Revenue)	33,18,07,000	—	33,18,07,000
		(Capital)	1,67,000	—	1,67,000
21	Co-operation	(Revenue)	3,87,44,000	—	3,87,44,000
		(Capital)	1,06,16,000	—	1,06,16,000
22	Food and Ware-housing	(Revenue)	6,28,01,000	—	6,28,01,000
		(Capital)	10,34,00,000	—	10,34,00,000
23	Water and Power Development	(Revenue)	27,66,67,000	—	27,66,67,000
		(Capital)	51,81,67,000	—	51,81,67,000
24	Stationery and Printing	(Revenue)	3,02,77,000	—	3,02,77,000
		(Capital)	7,17,000	—	7,17,000
25	Road, Water Transport and Civil Aviation	(Revenue)	8,64,86,000	—	8,64,86,000
		(Capital)	5,44,95,000	—	5,44,95 000
26	Tourism and Hospitality Organisation	(Revenue)	1,96,51,000	—	1,96,51,000
		(Capital)	1,36,67,000	—	1,36,67,000
27	Labour and Employment	(Revenue)	3,84,59,000	—	3,84,59,000
		(Capital)	47,00,000	—	47,00,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	53,01,72,000	—	53,01,72,000
		(Capital)	29,10,87,000	—	29,10,87,000
29	Finance	(Revenue)	80,09,16,000	1,83,97,22,000	2,64,06,38,000
		(Capital)	—	50,98,20,000	50,98,20,000
30	Loans to Government Servants	(Capital)	7,62,17,000	—	7,62,17,000
31	Tribal Development	(Revenue)	46,33,83,000	—	46,33,83,000
		(Capital)	21,24,85,000	—	21,24,85,000
		Grand Total	11,02,87,50,000	2,37,13,05,000	13,40,00,55,000
		(Revenue)	9,03,66,39,000	1,86,14,85,000	10,89,81,24,000
		(Capital)	1,99,21,11,000	50,98,20,000	2,50,19,31,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 206 of the constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly for the months of April to July, 1998 of the financial year 1998-99 pending the completion of the procedure prescribed in article 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes for the year 1998-99.

The regular Budget is to be passed by the Legislative Assembly in July, 1998. As such the vote on account is being obtained for April to July, 1998.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 30th March, 1998.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A. C. (1)-1/98]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1998, recommends, under article 207 of the Constitution of India the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1998

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year, 1998-99.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR
Secretary (Law).

SHIMLA:
The 30th March, 1998.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।